महत्वपूर्ण एवं खास

शिक्षकों के 14 हजार 580 पदों पर सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की सहमति

रायपुर (आरएनएस)। राज्य शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों की 14 हजार 580 पदों पर सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की सहमति प्रदान कर दी है। यह सहमति वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर दी गई है। आज यहां मंत्रालय से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस आशय का आदेश जारी किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को जारी आदेश में कहा गया है कि नियुक्ति आदेश व्यक्तिगत जारी किए जाएं, नियुक्ति आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि प्रोबेशन अवधि तथा प्रोबेशन अवधि में देय वेतन वित्त विभाग के वित्त निर्देश क्रमांक 21/2020 के अनुसार होगा।

दोस्त के घर फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या

कोरबा (आरएनएस)। बालको नेहरू नगर वार्ड नंबर 40 में एक युवक ने अपने दोस्त के घर मे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि रजगामार निवासी गोपी राम 27 वर्ष जो कुछ समय से कोरबा सुभाष ब्लाक में निवासरत था जो बालको ठेका कंपनी में कार्यरत था। कल रात अपने दोस्त काजू के घर बालको पहुचा काजू को रात्रि पाली की ड्यूटी करना था वह अपने यह आये मित्र को बोलकर काम करने चला गया। जब लौट तो देखा उसका दोस्त गोपी दास छत में फंद्दा बनाकर झूल गया है। काजू ने इसकी सूचना पुलिस को दी पुलिस मौके पर पहुचकर आगे की कार्यवाही कर रही है।

किशोरी का अपहर्ता गिरफ्तार

कोरबा (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश से वापस लौट रहे किशोरी के अपहर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज शाम रिमांड पर न्यायालय पेश किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पसान थाना अंतर्गत पिपरिया सीपत पारा क्षेत्र से एक किशोरी को वर्ष 2019 में वृंदावन उत्तर प्रदेश निवासी युवक अनिल कुमार उम्र 23 वर्ष बहला फुसलाकर भगा ले गया था। उस दौरान किशोरी को किसी तरह से पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया था। जबकि आरोपी फरार हो गया था। इस मामले में पसान पुलिस फरार आरोपी की लगातार सरगर्मी से तलाश कर रही थी। लेकिन उसका कोई ठोस ठिकाना नहीं मिलने के कारण वह पुलिस पकड़ में नहीं आ पा रहा था। इसी बीच कोरबी से पुलिस के एक मुखबीर ने कल शाम पसान थाने के प्रभारी उपनिरीक्षक प्रहलाद राठौर को यह जानकारी दिया कि पसान थाने के अपहरण मामले का फरार आरोपी कोरबी चौक में बस से उतर रहा है। पसान थाना प्रभारी ने तत्काल आरक्षक कौशल प्रसाद बुद्ध सिंह मधुकर तथा विकास कोसले को रवाना किया। वहां पहुंचते ही पुलिस कर्मियों ने आरोपी को धरदबोचा। जिसके विरूद्ध अपराध क्रमांक 35-21धारा 363 के मामले में विधि सम्मत वैधानिक कार्रवाई पूर्णकर उसे रिमांड पर न्यायालय भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

अवैध नशीली दवाइयों के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

सूरजपुर (आरएनएस)। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता को जानकारी मिली कि जिला कोरिया की ओर से स्वीफ्ट कार में कुछ लोग नशीली दवाई लेकर सूरजपुर की ओर आ रहे है। पुलिस अधीक्षक ने नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की धरपकड़ के लिए तत्काल पुलिस की ज्वाईंट टीम को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। ज्वाईन्ट टीम के द्वारा कमलपुर चौक धनेशपुर मोड़ के पास घेराबंदी कर एक स्वीफ्ट डिजायर कार को रोकवाया जिसमें जिला कोरिया के सब्बीर अहमद, अयाज खान व तारीक अहमद मिले जिनके कब्जे से 50 नग रिलेक्स कॉफकफ सिरप एवं स्पास्मो टेबलेट 696 नग जप्त किया गया जिसकी बाजारू कीमत 50 हजार रूपये है। पुलिस ने नशीली दवाई एवं परिवहन में प्रयुक्त स्वीफ्ट डिजायर कार सीजी 29 ए 0251 जप्त करते हुए तीनों के विरूद्ध धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया ।

छत्तीसगढ़ में जीएसटी संग्रहण में 33 प्रतिशत की वृद्धि

» राज्य में हुई वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर हुई कुल वृद्धि से ज्यादा

» अनेक राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ ने जीएसटी संग्रहण में ज्यादा ग्रोथ किया

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में जुलाई 2021 में 2,432 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण हुआ है, जो वर्ष 2020 की इसी अवधि से 33 प्रतिशत अधिक है। जुलाई 2020 में 1832 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण राज्य में हुआ था। जीएसटी संग्रहण में हुई यह वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर कुल जीएसटी संग्रहण में हुई 32 प्रतिशत वृद्धि से ज्यादा है।

केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में जीएसटी संग्रहण में हुआ ग्रोथ मध्यप्रदेश के 16 प्रतिशत, कर्नाटक के 12 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश के 18 प्रतिशत, बिहार के 21 प्रतिशत, पंजाब के 29 प्रतिशत, उत्तराखंड के 12 प्रतिशत, राजस्थान के 12 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल के 15 प्रतिशत, केरल के 27 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश के 28 प्रतिशत की तुलना में अधिक है।

उल्लेखनीय है कि कोरोना-संकट की चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के बावजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बनी रही है। लाकडाउन के बावजूद कृषि और वन क्षेत्रों में निर्बाध रूप से काम चलता रहा है। इसी दौरान शुरु हुई राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को आर्थिक संबल मिला है। पिछले वर्ष प्रदेश के करीब 19 लाख किसानों को योजना का लाभ मिला था, जबकि इस वर्ष 22 लाख किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। इन किसानों ने पिछले सीजन के दौरान धान का विपुल उत्पादन का रिकार्ड कायम किया था। इस बार लाभान्वित हो रहे किसानों के खातों में आदान सहायता राशि की पहली किस्त के 1500 करोड़ रुपए भी जारी किए जा चुके हैं। चालू सीजन के लिए योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब और भी अधिक किसानों को इसमें शामिल किया गया है। वनोपज संग्रहण के मामले में भी छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल रहा। वनोपजों के वैल्यू एडीशन और गौठानों में चलने वाली आजीविका गतिविधियों से प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर निर्मित हुए हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार रोजगार मुहैया कराए गए। गोधन न्याय योजना के माध्यम से 2 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही गोबर खरीदी, जैविक खाद के निर्माण और बिक्री से भी बड़ी संख्या में किसान, पशुपालक तथा स्व सहायता समूह के सदस्य लाभान्वित हुए हैं।

राजधानी में डेंगू का प्रकोप बढ़ा,नगर निगम अमला कर रहा है एंटीलार्वा का छिड़काव

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शहर के 6 और मोहल्लों में डेंगू के और नए मरीज मिले है। मरीजों की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। नगर निगम अमला जोन स्तर एंटीलार्वा के छिड़काव शुरु कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार शहर के रामनगर इलाके में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए है। जिसके बाद अब निगम सख्त हुआ है। इलाके में एंटीलार्वा का छिड़काव किया जा रह है। वहीं मौदहापारा,छोटा रामनगर,गांधीनगर ,आर्दशनगर ,कालीबाड़ी बस्ती,देवेन्द्र नगर डेंगू का प्रकोप फैलने से बहुत सारे लोग बीमार है। निगम अलर्ट होकर डेंगू प्रभाव वाले क्षेत्र में फागिंग कार्य करने के साथ-साथ घर-घर जा-जाकर कूलरों का पानी खाली करवा रही है। बता दे कि 40 नए मरीजों की पुष्टि के बाद कुल मरीजों की संख्या 70 हो गई है।

नक्सलियों ने की युवक की हत्या

धमतरी (आरएनएस)। नक्सलियों ने फिर एक बार नगरी थाना क्षेत्र के ग्राम चंदनबाहरा में एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों ने अब तक मुखबिरी के शक पर करीब पांच ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा है। ऐसे में नक्सली गतिविधियों को हत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन के समक्ष चुनौती खड़ी हो गई है।

गौरतलब है कि नक्सलियों की ओर 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि वे लोगों के बीच दहशत कायम करने तथा अपने गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। पिछले दिनों वनांचल क्षेत्र के ग्राम कारीपानी में शहीद सप्ताह का बैनर पोस्टर फेंककर दहशत फैलाने का प्रयास किया।

हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर बैनर पोस्टर तो हटा लिया, लेकिन नक्सली उनके हाथ नहीं लगे। शायद यही वजह है कि उनके हौसले बुलंद हैं। बहरहाल नक्सलियों की लगातार गतिविधियां होने से आसपास के ग्रामीणों की नींद उड़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार हत्या की जानकारी मिलने पर एसपी प्रफुल्ल ठाकुर समेत आला अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। मौका मुआयना कर आसपास के ग्रामीणों से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। आसपास के जंगलों में सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है।

हावड़ा एवं टिकियापारा यार्ड में जलभराव के कारण दपूमरे से होकर चलने वाली कई गाड़ियां रहेगी प्रभावित

रायपुर (आरएनएस)। दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा यार्ड एवं टिकियापारा यार्ड में जलभराव के कारण अनेक गाड़ियों का परिचालन प्रभावित हो रहा है, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कई गाड़ियां प्रभावित रहेगी।

रेल मंडल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 30 जुलाई को हावड़ा से चलने वाली गाड़ी संख्या 02470 हावड़ा-सीएसएमटी स्पेशल रद्द रहेगी, 30 जुलाई को हावड़ा से चलने वाली गाड़ी संख्या 02096 हावड़ा-सीएसएमटी दुरन्तो स्पेशल, 29 जुलाई को हावड़ा से चलने वाली गाड़ी संख्या 02834 हावड़ा-अहमदाबाद स्पेशल, 01 अगस्त को सीएसएमटी से चलने वाली गाड़ी संख्या 02469 सीएसएमटी-हावड़ा स्पेशल एवं 01 अगस्त 2021 को सीएसएमटी से चलने वाली गाड़ी संख्या 02095 सीएसएमटी-हावड़ा दुरन्तो स्पेशल रद्द रहेगी।

इसी प्रकार गंतव्य से पहले समाप्त होने वाली गाड़ियां में 29 जुलाई को सीएसएमटी से चलने वाली गाड़ी संख्या 02259 सीएसएमटी-हावड़ा स्पेशल हावड़ा के स्थान पर सांतरागाछी स्टेशन में समाप्त होगी। 29 जुलाई 2021 को अहमदाबाद से चलने वाली गाड़ी संख्या 02833 अहमदाबाद-हावड़ा स्पेशल हावड़ा के स्थान पर सांतरागाछी स्टेशन में समाप्त होगी। 29 जुलाई 2021 को सीएसएमटी से चलने वाली गाड़ी संख्या 02095 सीएसएमटी-हावड़ा दुरन्तो स्पेशल हावड़ा के स्थान पर सांतरागाछी स्टेशन में समाप्त होगी।

इस प्रकार 30 जुलाई 2021 को हावड़ा से चलने वाली गाड़ी संख्या 02834 हावड़ा-अहमदाबाद स्पेशल हावड़ा के स्थान पर सांतरागाछी स्टेशन से प्रारम्भ होगी, 30 जुलाई 2021 को हावड़ा से चलने वाली गाड़ी संख्या 02810 हावड़ा-सीएसएमटी स्पेशल हावड़ा के स्थान पर सांतरागाछी स्टेशन से प्रारम्भ होगी। 30 जुलाई 2021 को हावड़ा से चलने वाली गाड़ी संख्या 02280 हावड़ा-पुणे स्पेशल हावड़ा के स्थान पर सांतरागाछी स्टेशन से प्रारम्भ होगी।

प्रदेश में 30 जुलाई को कोरोना संक्रमण की दर 0.29 प्रतिशत और 31 जुलाई को 0.26 प्रतिशत रही

» कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए प्रदेश में अब तक 1.14 करोड़ सैंपलों की जांच

» प्रति दस लाख की आबादी में रोजाना 1487 सैंपलों की जांच, राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 1306

रायपुर (आरएनएस)। राज्य शासन द्वारा कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए किए गए प्रभावी उपायों से संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। प्रदेश में 30 जुलाई को संक्रमण की दर घटकर 0.29 प्रतिशत पर पहुंचने के बाद 31 जुलाई को इसमें और गिरावट आई है। 31 जुलाई की स्थिति में संक्रमण की दर 0.26 प्रतिशत पर पहुंच गई है। प्रदेश के तीन जिलों में कोविड-19 का कोई नया मरीज नहीं मिला है। इनमें बेमेतरा, कबीरधाम और गरियाबंद शामिल हैं। इस दिन प्रदेश में कोविड-19 से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। प्रदेश भर में 30 जुलाई को 42 हजार 714 सैंपलों की जांच में 125 और 31 जुलाई को 38 हजार 644 सैंपलों की जांच में 102 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने और रोज कम संख्या में नए मरीज मिलने के कारण कोविड-19 के सक्रिय मामले भी तेजी से घट रहे हैं। राज्य में अभी सक्रिय मरीजों की संख्या 1863 है।

प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए अब तक एक करोड़ 13 लाख 94 हजार 233 सैंपलों की जांच की गई है। कोरोना संक्रमण की शुरूआत से लेकर अब तक प्रति दस लाख की आबादी में औसत कोरोना जांच और रोजाना प्रति दस लाख की आबादी में कोरोना जांच में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय औसत से आगे है। प्रदेश में प्रतिदिन प्रति दस लाख की जनसंख्या में 1487 सैंपलों की जांच की जा रही है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 1306 है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरूआत के बाद से अब तक प्रति दस लाख की आबादी में तीन लाख 95 हजार 335 सैंपलों की जांच की गई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत तीन लाख 42 हजार 961 है।

राज्य में अब तक 582.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून 2021 से अब तक राज्य में 582.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून से आज 1 अगस्त तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार कोरबा जिले में सर्वाधिक 892.2 मिमी और बालोद जिले में सबसे कम 419 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सरगुजा में 488.6 मिमी, सूरजपुर में 695 मिमी, बलरामपुर में 659.5 मिमी, जशपुर में 612.9 मिमी, कोरिया में 569.2 मिमी, रायपुर में 510.6 मिमी, बलौदाबाजार में 618.3 मिमी, गरियाबंद में 509.1 मिमी, महासमुंद में 504.8 मिमी, धमतरी में 490 मिमी, बिलासपुर में 640 मिमी, मुंगेली में 598.2 मिमी, रायगढ़ में 527.3 मिमी, जांजगीर चांपा में 627 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 652.6 मिमी, दुर्ग में 522.7 मिमी, कबीरधाम में 492.2 मिमी, राजनांदगांव में 438.7 मिमी, बेमेतरा में 713.7 मिमी, बस्तर में 447.3 मिमी, कोण्डागांव में 548.9 मिमी, कांकेर में 481.4 मिमी, नारायणपुर में 651.2 मिमी, दंतेवाड़ा में 509.3 मिमी, सुकमा में 863.4 और बीजापुर में 623 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड की गई।

अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूएनसीसीडी द्वारा वनमंत्री अकबर हुए सम्मानित

» छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के संरक्षण व संवर्धन के कार्यों की सराहना

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कंबैट डिजरटी फिक्रेशन संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय करण रोकथाम कन्वेंशन (यूएनसीसीडी) द्वारा की गई है। उक्त संस्था यूएनसीसीडी द्वारा इसके तहत वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर और छत्तीसगढ़ राज्य के पारंपरिक वैद्य संघ के प्रांतीय सचिव निर्मल अवस्थी को सम्मानित किया गया है। यूएनसीसीडी की टीम ने वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के विषय में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान और छत्तीसगढ़ राज्य के पारंपरिक वैद्य संघ के प्रांतीय सचिव अवस्थी को होम हर्बल गार्डन योजना के तहत औषधीय पौधों का ज्ञान तथा पारंपरिक ज्ञान आधारित चिकित्सा पद्धति के पुनरुत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है।

यूएनसीसीडी सचिवालय के मिस्टर रजेब बुलहारौत ने इसकी सरहाना करते हुए उन्हें सर्टिफिकेट जारी कर सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के 4800 पारंपरिक वैद्यों ने इस का स्वागत किया है और सभी में हर्ष व्याप्त है। परंपरागत वनौषधि प्रशिक्षित वैद्य संघ छत्तीसगढ़ के प्रांतीय कोषाध्यक्ष अवधेश कश्यप ने बताया कि प्रतिवर्ष औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण कर छत्तीसगढ़ राज्य की लोक स्वास्थ्य परंपरा, संवर्धन अभियान एवं घर अंगना जड़ी-बूटी बगिया योजना के तहत जन-जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। प्रदेश के पारंपरिक वैद्यों के द्वारा मौसमी बीमारियों के अलावा असाध्य रोगों में जीवनीदायिनी वनौषधियों जिसमें ब्राम्ही अश्वगंधा, सतावर, तुलसी, कालमेघ, गिलोय, अडूसा, चिरायता, पत्थर चूर, मंडूपपर्णी, भुईआवला, भृंगराज, हडजोड आदि बहुउपयोगी वनौषधियों का वितरण किया जाता है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य क्षत्र में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्धन्य विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

मंत्री भेंड़िया ने ली दिव्यांगजन राज्य सलाहकार बोर्ड की वर्चुअल बैठक

» दिव्यांग कल्याण के लिए बनी राज्य दिव्यांग नीति

» प्रदेश में दिव्यांगजन के लिए आरक्षित सभी पदों पर भर्ती की कार्यवाही के निर्देश

» प्रदेश में 21 श्रेणी की दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन के सर्वेक्षण का काम 3 दिसम्बर तक पूरा करने के निर्देश

रायपुर (आरएनएस)। समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंड़िया ने आज राजधानी फॉरेस्ट कॉलोनी स्थित अपने आवास कार्यालय में दिव्यांगजन राज्य सलाहकार बोर्ड की वर्चुअल बैठक ली। बैठक में उन्होंने राज्य के सभी शासकीय विभागों में छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजन के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार रिक्त पदों की पहचान कर उनमें शीघ्र भर्ती के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से समन्वय करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी दिव्यांगजन तक पहुंचकर शत-प्रतिशत विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड) बनाने के निर्देश दिए हैं जिससे उन तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। बैठक में अधिकारियों ने बताया गया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य दिव्यांग नीति तैयार कर ली गयी है। जिसका प्रकाशन किया जाना है। श्रीमती भेंड़िया ने राज्य दिव्यांग नीति के शीघ्र प्रकाशन के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं।

श्रीमती भेंड़िया ने प्रदेश में 21 क्षेणी के दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन के सर्वेक्षण का काम इस साल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसम्बर तक पूरा करने कहा है, जिससे दिव्यांगों का डाटाबेस तैयार किया जा सके। विभाग द्वारा 1 अगस्त से 31 अगस्त तक स्वावलंबन मास का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान यूडीआईडी कार्ड बनाने में ऐसे जिले जिनकी प्रगति राज्य की औसत प्रगति से कम है उन्हें पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयन कर स्वावलंबन मास में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिए अभियान चलाया जाएगा। श्रीमती भेंड़िया ने नाराजगी व्यक्त करते हुए दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड बनाने के काम को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सभी चिन्हांकित दिव्यांगों तक पहुंचकर उनके यूडीआईडी कार्ड बनाए जाए। उन्होंने सभी संभागों में मानसिक रोगियों के लिए शीघ्र हाफ वे होम शुरू करने भी कहा।